हिन्दी दैनिक
पथ प्रवाह
RNI No.: UTTHIN/2011/39282
हर खबर पर पैनी नजर

वर्ष:4 अंक:273 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, मंगलवार, 07 अक्टूबर 2025

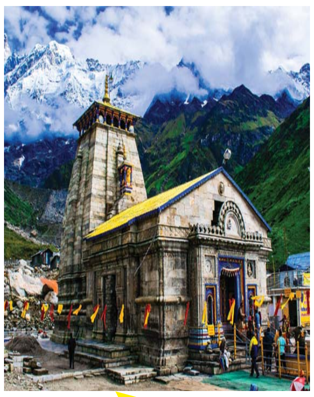

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 1.20 करोड़ की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण

‘राइजिंग टिहरी – फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग क्लास’ का शुभारंभ, अब गांवों में होगी जेईई–नीट की तैयारी

पथ प्रवाह, देहरादून

ऋषिकेश में आयोजित सरस आजीविका मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय महासंघ (सी.एल.एफ.) के लिए 1.20 करोड़ रुपये की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 10 अन्य सी.एल.एफ. के लिए 1 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों का शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर ‘राइजिंग टिहरी - फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग क्लास’ का भी शुभारंभ किया गया, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों के युवा जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने गांव में रहकर ही कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ग्रामोत्थान परियोजना के तहत ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। उन्होंने मेले में उपस्थित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि यह मेला ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास है। आजीविका मेलों के माध्यम से न केवल स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है, बल्कि ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘लोकल के लिए वोकल’ के मंत्र को भी साकार करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

ऐसे मेलों के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमियों तथा कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जा रहा है। मेले में लगाए गए स्टॉल ‘स्वदेशी अपनाओ’ के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे अपने गांव, प्रदेश और देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का संकल्प सुदृढ़ हो रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद खरीदना केवल एक सामान की खरीद नहीं, बल्कि ग्रामीण कारीगरों, मातृशक्ति और उद्यमियों के सपनों में निवेश है। स्वदेशी अपनाने से न केवल संस्कृति और परंपरा जीवित रहती है, बल्कि किसानों, हस्तशिल्पियों और स्थानीय उद्यमियों की आजीविका भी सशक्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आह्वान को आत्मसात करते हुए आज मातृशक्ति ने स्वदेशी उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। स्वयं सहायता समूहों की दीदियाँ अपने श्रम और कौशल से स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिला रही हैं। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत अब तक 1.65 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बनी हैं। ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ के अंतर्गत महिलाओं ने लगभग 2000 स्टॉल लगाकर 5.5 करोड़ रुपये का विपणन किया है। साथ ही, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्वदेशी उत्पाद अब विश्व स्तर तक पहुंच रहे हैं।

राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 68 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। 7,500 से अधिक ग्राम संगठन और 534 क्लस्टर स्तरीय संगठन भी स्थापित किए गए हैं।

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ‘महिला किसान सशक्तिकरण योजना’ और ‘फार्म जीविकोपार्जन योजना’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार काम कर रही है। इन योजनाओं के तहत राज्य की 3 लाख से अधिक महिला किसानों की क्षमता व कौशल विकास किया गया है। 2.5 लाख पोषण उद्यान और रसोई बागवानी स्थापित किए गए हैं, साथ ही 500 कृषि यंत्र बैंक भी उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य में 5 हजार से अधिक महिला किसानों को जैविक खेती से जोड़ा गया है।

इन प्रयासों से प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज मातृशक्ति आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है, जो इस सरस मेले में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, ग्रामीण उद्यमी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुख्यमंत्री आवास में की भेंट

पथ प्रवाह, संवाददाता, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक और राज्य हित से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने राज्य के विकास, शासन की प्रक्रिया, विधानसभा के संचालन एवं जनहितकारी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने नागरिकों के कल्याण और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के अनुभव और मार्गदर्शन की सराहना की, वहीं ऋतु खंडूरी ने राज्य सरकार की नीतियों एवं जनकल्याणकारी पहलों की प्रशंसा की। इस सौहार्दपूर्ण बैठक को राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों और

प्रशासनिक समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ अधिकारी एवं सचिवालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म

अल्पसंख्यक शिक्षा अब मुख्यधारा से जुड़ने की ओर, राज्यपाल ने विधेयक पर लगाई मुहर

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ अब राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। साथ ही, इन्हें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (उत्तराखंड बोर्ड) से संबद्ध होना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को ÷शिक्षा में समानता और आधुनिकता की दिशा में मील का पत्थर÷ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर बच्चा –चाहे वह किसी भी वर्ग, मजहब या समुदाय का हो – समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जुलाई 2026 के सत्र से राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) और नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को मुख्यधारा की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों में समान लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा है। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल शिक्षा में सुधार लाएगा, बल्कि सामाजिक एकता और समान अवसरों को भी नई दिशा देगा।

डीएम सविन बंसल की जन सुनवाई में 121 शिकायतें दर्ज, भूमि धोखाधड़ी पर सख्त

पथ प्रवाह, संवाददाता, देहरादून

जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जन सुनवाई में जन शिकायतें सुनीं। ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, आर्थिक सहायता, बिजली बिल, बाढ़ सुरक्षा और मुआवजा सहित 121 शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।

डीएम ने अधिकारियों को चेताया कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर समाधान सुनिश्चित करें।

भूमि धोखाधड़ी पर सख्त रुख

नवाकोट निवासी जयमल सिंह द्वारा भूमि अदला-बदली में कूटरचित हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की शिकायत पर डीएम ने एसडीएम को 15 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

विवादित भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के निर्देश

नेहरूग्राम निवासी सुषमा की शिकायत पर एमएनए नगर निगम को न्यायालय आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए।

दिव्यांग को मिला रोजगार का भरोसा

दिव्यांग गौरव कुमार के रोजगार प्रार्थना पर डीएम ने एएसडीएम को किसी कंपनी में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

आर्थिक सहायता और शिक्षा पर संवेदनशीलता

शैली गुप्ता ने पति की मृत्यु के बाद बच्चों की पढ़ाई पर संकट की बात रखी। डीएम ने सीडीओ व मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूल प्रबंधन से बात कर बच्चों की पढ़ाई जारी

रखने की व्यवस्था करने को कहा।

आपदा पीड़ितों को राहत के निर्देश

फूलेत माजरा, भैकली खाल और सैबूवाला के ग्रामीणों की आपदा क्षति पर डीएम ने तहसीलदार और एसडीएम को त्वरित मुआयना कर राहत वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश

हर्रावाला, रानीपोखरी और डालनवाला में अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतों पर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

संवेदनशील और समाधानपरक प्रशासन की झलक

डीएम सविन बंसल ने कहा कि जन सुनवाई शासन की रीढ़ है, और इसका उद्देश्य लोगों को न्याय और राहत समय पर दिलाना है।

जनता दरबार में एसडीएम अपूर्वा सिंह, कुमकुम जोशी, विनोद कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वी.के. ढौंडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की जनसुनवाई, 28 समस्याओं का मौके पर कराया निस्तारण

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिसमें 28 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि विवाद, अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल, विद्युत आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई।

जनसुनवाई कार्यक्रम में प्राथी गुलशाना निवासी ग्राम बंदरजुड़ तहसील भगवानपुर ने खसरा न 335 - खाता नं 135 की भूमि पर मकान का निर्माण कर रहा है जिसको वन विभाग द्वारा रोका जा रहा है जिसको लेकर प्रार्थना पत्र दिया।रणधीर सिंह निवासी नाथनगर ज्वालापुर ने भूमि खाता संख्या 69 खसरा नं 211 (ग) में बदोबस्त अधिकारी का आदेश हुआ था, जिसको खतौनी में चढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इनामु अली पुत्र अली हसन ग्राम हजारा ग्रंट ने खेत खसरा नं 859 ग्राम हजारा ग्रंट ब्लॉक बहादराबाद रुड़की की जो चक रोड के दक्षिण में स्थित रकबा कुल रकबा 6 बीघा है जिला पंचायत हरिद्वार ने रोड का निर्माण कराया था चक रोड से कोई भी पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं कराया गया था जिसके कारण प्राथी के भूमि में जलभराव हो गया था जिसको लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया।पंकज सैनी निवासी कृष्णा नगर ने अपनी दुकान के सामने रोड के बीचों बीच एल टी का विद्युत पोल को स्थानांतरित कराने के लेकर प्रार्थना पत्र दिया। भूपेंद्र सैनी रावली महदूद ने जय श्री धर्म कांटे सिडकुल से लेकर बैरियर नं 6 तक तक मुख्य मार्ग पर हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में शिकायत की गई।रेशमा पत्नी महबूब निवासी डालूवाला कलां ने अपने दोनों बच्चों का नाम किसी दूसरे के राशन कार्ड में दर्ज हो गया है,जिसको सही कराने को लेकर प्रथम पत्र दिया। बोहाती पत्नी स्व नेत्रपाल मौजा ग्राम कुमाराडा परगना मंगलौर तहसील रुड़की ने अपनी भूमि पैमाईश करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।सुशील कुमार ग्राम बनजारे वाला में ग्राम समाज की जलमग्न भूमि जिसका खसरा नं 578 है उसमें कुछ लोगो द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे हटवाने को लेकर शिकायत की गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं स्थिलता नहीं होनी चाहिए, स्थिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का करें निस्तारण

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्पलाइन में जो भी शिकायतें दर्ज हो रही है उसे समयबद्धता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करे तथा आवेदनकर्ता से भी दूरभाष के माध्यम से वार्ता करते हुए शिकायत का निस्तारण तत्परता से किया जाए।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ,अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी,उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार,जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश,मुख्य वित्त अधिकारी अजय कुमार,जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह,जिला अर्थ संख्या आधिकारी नलिनी ध्यानी, ,मुख्य क्रीड़ा अधिकारी शैफाली गुरांग, डीएसओ तेजबल सिंह,जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत,अपर निर्देशक मत्स्य विभाग गरिमा मिश्रा, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

एक नजर

केबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की, त्वरित पुनर्निर्माण के दिए निर्देश

पथ प्रवाह, देहरादून। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों की विशेष बैठक की। बैठक में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों, पुलों, सी.सी. पैच, जलापूर्ति और विद्युत व्यवस्थाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी कार्य तत्काल और ठोस कार्रवाई के साथ किए जाएं।

मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र इस्तीमेट तैयार करके शासन को भेजने और आपसी समन्वय बनाकर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभागीय अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें ताकि किसी भी आपदा प्रभावित को परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग अपनी कार्ययोजना को जल्द से जल्द तैयार करें और उसे धरातल पर उतारें। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुविधाओं की बहाली में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, अनुज कौशल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान राजेंद्र पाल, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल राकेश कुमार, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग सुरेश चंद्रा, संदीप मित्तल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मोहित सैनी अध्यक्ष और सत्या कुमार चुने गए वन बीट अधिकारी संघ के महामंत्री

पथ प्रवाह, दीपक चौहान। वन बीट अधिकारी संघ शाखा हरिद्वार का द्विवार्षिक अधिवेशन नगर वन हरिद्वार में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के दौरान नई कार्यकारिणी की चयन भी किया गया। नए कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों को सर्व सम्मति से निर्विरोध चुना गया। अध्यक्ष अरविन्द सैनी सहायक वन कर्मचारी संघ हरिद्वार की अध्यक्षता में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया में मोहित सैनी को अध्यक्ष और सत्या कुमार को निर्विरोध महामंत्री चुना गया। इसके अलावा निर्विरोध चुने गए अन्य पदाधिकारी और सदस्यों में उपाध्यक्ष दुष्यंत सैनी, कोषाध्यक्ष राहुल नेगी, संरक्षक मंत्री सत्यवीर सिंह, संगठन मंत्री परमजीत राठौर, मीडिया प्रभारी गौतम भारती, महिला उपाध्यक्ष हेमा यादव, संयोजक मंत्री अभिषेक नौटियाल, सम्प्रेक्षक अजीत सिंह और मोनू कुमार को चुना गया। नई कार्यकारिणी को समस्त सदस्यों ने बधाई दी।

उत्तराखंड में मंडुवा की खरीद शुरू, किसानों की आय और पौष्टिक आहार में बढ़ावा

211 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से 48.86 रुपये प्रति किलो पर मंडुवा खरीदा जाएगा

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर की 211 सहकारी समितियों के माध्यम से मंडुवा की खरीद शुरू कर दी है। इस वर्ष मंडुवा का समर्थन मूल्य 48.86 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। इस निर्णय से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और लोगों को पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार भी मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मिशन के तहत मंडुवा और अन्य मिलेट्स को सीधे किसानों से खरीदकर बाजार तक पहुंचाने के साथ उनकी आय दोगुनी करने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष राज्य सहकारी संघ ने 50,000 कुंतल मंडुवा खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19,000 कुंतल अधिक है। डॉ. रावत ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि मोटा अनाज जैसे मंडुवा के माध्यम से उत्तराखंड के किसान अपनी आय बढ़ाएं और यह उत्पाद लोकल से ग्लोबल स्तर तक पहुंचे। राज्य सहकारी संघ मिलेट्स एवं पहाड़ी उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारने जा रहा है। मंडुवा की कीमत पहले 18 रुपये प्रति किलो थी, जो अब 48.86 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। यह किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी आमदनी बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। राज्य सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ला ने बताया कि 1 अक्टूबर से मिलेट्स की खरीद शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष प्रति कुंतल मंडुवा 4,886 रुपये में खरीदा जा रहा है और प्रत्येक कुंतल पर समिति को 100 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने राशन डीलर्स के भुगतान पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

पथ प्रवाह, देहरादून

प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में राशन डीलर्स के भुगतान और अन्य समस्याओं पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखंड के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने लाभांश और भाड़े के भुगतान न होने संबंधी राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग 2024 तक के सभी बकाया का भुगतान सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिलों में समान्तर रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। मंत्री ने फेडरेशन को आश्वासन दिया कि भारत सरकार की ओर से प्राप्त बजट के बाद सभी जिलों का भुगतान एकसमान रूप से किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड के समय के भाड़े का भुगतान भी शीघ्र किया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने गोदामों में धर्मकांटा और वेविंग मशीन लगाने हेतु परीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि गोदाम की क्षमता के अनुसार मशीनों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, ई-पॉज मशीनों में आ रही दिक्कतों के लिए तकनीकी स्टाफ बढ़ाने के भी आदेश दिए गए।

वृद्ध महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई पहल: मंत्री रेखा आर्या ने तैयार की कार्ययोजना

पथ प्रवाह, देहरादून

प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य वृद्ध और असहाय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई कार्ययोजना तैयार करना था। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एक रूपये सेस के माध्यम से एकत्रित धनराशि का उपयोग वृद्ध महिलाओं की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ उनके आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों और वृद्ध महिलाओं के कल्याण में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों को साथ मिलकर योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्य ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना प्रदेश की वृद्ध और असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अभिनव एवं नवीन प्रयास है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में जनपदवार छोटे-छोटे महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जहां वृद्ध महिलाओं से सीधे संवाद किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह योजना जल्द ही अपना पूर्ण स्वरूप ले और वृद्ध महिलाओं के साथ सरकार एक पारिवारिक सदस्य के रूप में खड़ी रहे। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अधिकारी विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, नीतू फुलेरा सहित अन्य विभागीय अधिकारी और एनजीओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जगतगुरु आश्रम कनखल में महाकवि कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन

काव्य–साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति पर आधारित संगोष्ठी में विद्वानों ने व्यक्त किए विचार, महाकवि की रचनाओं पर विमर्श ने युवा साहित्यकारों को प्रेरित किया

पथ प्रवाह, संवाददाता, नवीन चौहान

कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में सोमवार को महाकवि कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह की काव्य-साहित्य साधना पर आधारित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी महाराज, डॉ चन्द्रपाल शर्मा, शशि प्रकाश सिंह, प्रो. डॉ सुनील कुमार बत्रा एवं डॉ गजेन्द्र सिंह भदोरिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र में शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने महाकवि कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह को न केवल एक सशक्त साहित्यकार बताया, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति के अग्रदूत के रूप में भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उनके काव्य में भारतीय जीवन-दर्शन की झलक मिलती है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह की कविताएं केवल शब्द नहीं, बल्कि राष्ट्र को दिशा देने वाले संदेश हैं। उन्होंने आशा जताई कि संगोष्ठी युवा साहित्यकारों को प्रेरित करेगी और उनके साहित्य पर विमर्श को नई दिशा प्रदान करेगी।

तकनीकी सत्रों में साहित्यिक विमर्श का समृद्ध मंच

प्रथम तकनीकी सत्र में प्रो. डॉ चन्द्रपाल शर्मा ने कुँवर जी द्वारा रचित रामकाव्य में मौलिकता, नवीनता और संतुलित दृष्टिकोण को उजागर किया। उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस से तुलना करते हुए बताया कि कुँवर जी ने रामकाव्य में नूतन कल्पनाओं और दर्शनशास्त्र का उत्कृष्ट समावेश किया। प्रो. सुनील कुमार मिश्रा ने उनके नाट्य साहित्य और शाश्वत मूल्यों को स्पष्ट किया, जबकि डॉ मोना शर्मा ने उनकी रचनाओं की गहनता और उसमें छिपे साहित्यिक रत्नों की चर्चा की।

द्वितीय तकनीकी सत्र में डॉ चन्दना शर्मा, डॉ लता शर्मा, डॉ अलका पाण्डेय, डॉ आशा शर्मा, डॉ रेणु सिंह और प्रो. दिनेश चमोला शैलेश आचार्य सहित अनेक विद्वानों ने महाकवि की रचनाओं में प्रतिफलित भावपक्ष, लोक चेतना, प्रेमभाव, वीरभाव, सौंदर्य चेतना, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति पर आधारित गहन विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान महाकवि की भक्ति भाव से पूर्ण रचनाओं और नाटकों पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में साहित्यकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और कवियों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। वरिष्ठ साहित्यकारों एवं शिक्षिकाओं ने अपने अनुभवों और विचारों का आकर्षक रूप में प्रस्तुतीकरण किया।

संगोष्ठी का उद्देश्य और महत्व

जगत गुरु आश्रम कनखल, मां सावित्री फाउंडेशन लखनऊ, अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति लखनऊ एवं एस.एम.जे.एन.पी.जी. कॉलेज हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस संगोष्ठी का उद्देश्य महाकवि कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह की रचनाओं में निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति मूल्य को युवा पीढ़ी तक पहुँचाना और उनकी रचनाओं पर शोध एवं विमर्श को प्रोत्साहित करना था। संगोष्ठी का समापन महाकवि की चर्चित कविताओं के पाठ और विद्वानों की टिप्पणी के साथ हुआ, जिसे उपस्थित श्रोताओं ने अत्यंत सराहा। यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक मील का पत्थर साबित हुआ।

हरिद्वार के नन्ने खिलाड़ियों में मुक्केबाजी का जोश और जूनून, 132 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हरिद्वार के योग स्थली स्टेडियम, रोशनाबाद में मुक्केबाजी के रिंग में जोश, ऊर्जा और खेल भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक आदेश चौहान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश गिरी, जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा एवं रोहन सहगल ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मुक्केबाजी जैसे खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ता का संचार करते हैं।

इस जोश भरी प्रतियोगिता में 132 खिलाड़ी (70 बालक और 62 बालिकाएं) ने भाग लिया और अपने शानदार पंचों से दर्शकों का दिल जीत लिया। जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष डा. विशाल गर्ग ने कहा कि ÷युवाओं में मुक्केबाजी के प्रति तेजी से रुझान बढ़ रहा है। संघ के प्रयासों से कई होनहार खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं, जो हरिद्वार और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुक्केबाजी न सिर्फ एक खेल है बल्कि आत्मरक्षा का सशक्त माध्यम भी है – विशेषकर बालिकाओं को इस खेल में प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए। रोमांचक मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन मिनी बालक वर्ग में रौनक, अद्विक, हर्षित, युवराज सैनी, सुधांशु, कमलप्रीत, अधिराज, अक्षिता और मौसम ने शानदार जीत दर्ज की। मिनी बालिका वर्ग में न्यास, दिव्या ज्योति, वर्षा, हिमांशी, इशिका और सौगात ने अपने-अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। सीनियर बालिका वर्ग में दिव्या, सुरभि, साक्षी, विदुषी शर्मा, प्रतिष्ठा चौधरी, हिमानी और सेम चौधरी ने रोमांचक जीत हासिल कर तालियां बटोरीं। मुख्य निर्णायक मंडल में नवीन चौहान, किशन सिंह महर, संगीत जोशी, अनिकेत और आशीष शर्मा शामिल रहे।

प्रतियोगिता के दौरान राकेश चौधरी, सुनीता चौधरी समेत अनेक खेलप्रेमी उपस्थित रहे जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से कराएं निराकरण: भगवत प्रसाद मकवाना

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने जिला कार्यालय सभागार में सफाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं सफाई कर्मचारियों के समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक की समीक्षा करते हुए उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवान ने एमएस एक्ट के तहत सफाई कर्मचारियों के सर्वेक्षण एवं पंजीकरण के संबंध में जानकारी चाही गई जिसपर नगर निगम,नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि सभा अधिकारी पूर्ण जानकारी के ही बैठक में उपस्थित हो, बिना तैयारियों एवं आधा अधूरी जानकारी के बैठक में सम्मिलित होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उन्हें हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। सीवरेज, रेलवे ट्रैक, नालियों एवं सेफ्टी टैंक में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को पीपी किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए साथ ही समय समय पर सभी सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए है कि सभी आउट सोर्स के सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए प्रतिदिन के मानदेय पर भुगतान किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को जो ठेकेदार द्वारा हटाए गए है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए तथा ठेकेदार द्वारा कम वेतन दिया जा रहा है संबंधित ठेकेदार से उसकी वसूली करते हुए उनको ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए है कि सफाई कर्मचारियों के जो रिक्त पद है उन पदों पर नियमानुसार तत्काल कर्मचारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए साथ ही सभी कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, एसपी (सदर) निशा यादव, एसीएमओ डॉ. अनिल वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया, जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर तालियान, प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला, राजेश राजोरिया, उत्तराखंड निकाय कर्मचारी सयुक्त मोर्चा के श्रमिक नेता सुरेंद्र तेश्वर, राजेंद्र श्रमिक सहित सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

एक नजर

धामी सरकार चली गरीब के द्वार, तीन गांवों में लगे बहुउद्देशीय शिविर

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति, उत्तराखंड सरकार देशराज कर्णवाल के नेतृत्व में ÷बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर÷ का ब्लॉक बहादराबाद के 3 गांवों में आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 39 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें पूरणपुर साल्हापुर में 28, मीरपुर में 6 और राजपुर में 5 शिकायतें मिली। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की जनसमस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करना तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना था। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और उत्साहपूर्वक अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं। इनमें कई समस्या एक जैसी थी। समस्याओं का समाधान शिविर स्थल पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया, जबकि कुछ जिला स्तर की समस्याएं थीं जिन्हें समाधान हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर देशराज कर्णवाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। शिविर में मण्डल अध्यक्ष रीता सैनी, प्रधान अनीता देवी, विजय पाल, सतीश कुमार, प्रधान कु. सोनी और सभी संबंधित रेखीय विभागों के अधिकारीगण व कर्मचारीगण ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यगण एवं क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

उत्तराखंड राज्य स्थापना को रजत जयंती सप्ताह में धूमधाम से मनाने की तैयारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शासन ने राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती सप्ताह के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई और सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए।

संपादकीय

उत्तराखण्ड पुलिस की निर्णायक कार्रवाई

उत्तराखण्ड में नशे के बढ़ते खतरों के बीच राज्य पुलिस ने पिछले तीन वर्षों में निरंतर और सशक्त कार्रवाई कर यह साबित कर दिया है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन का संकल्प अडिग है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अगस्त 2025 तक पुलिस ने 3431 मामलों में 4440 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए। इस कार्रवाई में 681.09 किग्रा चरस, 649.79 किग्रा डोडा, 61.22 किग्रा अफीम, 0.39 ग्राम कोकीन, 58.98 किग्रा हेरोइन, 4954.34 किग्रा गांजा, 7,20,278 गोलियां, 38,919 इंजेक्शन और 7,18,201 कैप्सूल शामिल हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 208 करोड़ रूपये से अधिक है।

विशेष रूप से एमडीएमए और अन्य सिंथेटिक दवाओं के बढ़ते प्रचलन ने पुलिस के समक्ष नई चुनौतियां पेश की हैं। राज्य की विशेष जांच टीमें (स्लम्र) और स्थानीय पुलिस ने चम्पावत, ऊधम सिंह नगर सहित कई जिलों में तस्करों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए एमडीएमए, प्रिकर्सर कैमिकल्स और अन्य अवैध पदार्थों की बड़ी मात्रा जब्त की। उदाहरण के लिए, चम्पावत जिले में अभियुक्त ईशा और राहुल कुमार से 5.688 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ, जबकि ऊधम सिंह नगर में अभियुक्त कुणाल राम कोहली से 7.41 ग्राम एमडीएमए और 650 लीटर से अधिक प्रिकर्सर कैमिकल्स जब्त किए गए।

सिर्फ तस्करों तक ही नहीं, बल्कि औद्योगिक और फार्मा कंपनियों की अवैध गतिविधियों पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। देहरादून में ग्रीन हर्बल फैक्ट्री से लाखों कैप्सूल, टेबलेट और सिरप बरामद किए गए। हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे गोदामों से 5 लाख से अधिक प्रतिबंधित कैप्सूल, शीशी और सिरप जब्त हुए। चंडीगढ़ एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में जे.आर. फार्मा कंपनी से 2.5 लाख प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई।

उत्तराखण्ड पुलिस की यह कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि नशा रोकथाम सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। पुलिस लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ के साथ-साथ समाज में जनजागरूकता फैलाने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसका उद्देश्य न केवल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना है, बल्कि युवाओं और आम जनता को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति सचेत करना भी है।

विश्लेषकों का मानना है कि नशा रोकथाम में प्रशासन और समाज का संयुक्त प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस का यह अभियान एक मजबूत संदेश देता है कि जब कानून व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता और सतत निगरानी साथ मिलकर काम करें, तो नशे जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

महर्षि वाल्मीकि: जिनकी वाणी में बसती है सम्पूर्ण सृष्टि

योगेश कुमार गोयल

अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन 'रामायण' के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अनुपम संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है और इस वर्ष वाल्मीकि जयंती 7 अक्तूबर को मनाई जा रही है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में उनकी जयंती रामायण काल से ही मनाई जा रही है। इस अवसर पर देशभर में कई प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषियों में से एक महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण को सबसे प्राचीन माना जाता है और संस्कृत के प्रथम महाकाव्य 'रामायण' की रचना करने के कारण ही उन्हें 'आदिकवि' के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मोक्षदायिनी रामायण आज भी समूचे विश्व में वेद तुल्य विख्यात है, जो 21 भाषाओं में उपलब्ध है और सनातन धर्म मानने वालों के लिए पूजनीय है। रामायण ने देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। राष्ट्र की अमूल्य निधि रामायण का एक-एक अक्षर अमरता का सूचक और महापाप का नाशक माना गया है। वाल्मीकि का रामायण महाकाव्य ज्ञान-विज्ञान, भाषा ज्ञान, ललित कला, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, इतिहास और राजनीति का केन्द्रबिन्दु माना जाता है। यह महाकाव्य श्रीराम के जीवन के माध्यम से जीवन के सत्य और कर्तव्य से परिचित कराता है। रामायण में जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने कई स्थानों पर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों की सटीक गणना की है, उससे स्पष्ट है कि वे ऐसे परम ज्ञानी थे, जिन्हें ज्योतिष विद्या तथा खगोल शास्त्र का भी बहुत गहन ज्ञान था।

रामायण को वैदिक जगत का सर्वप्रथम काव्य माना जाता है, जिसमें कुल चौबीस हजार श्लोक है। माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही इस दुनिया में पहले श्लोक की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा का जन्मदाता है। विभिन्न पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि महर्षि वाल्मीकि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोगों को लूटा करते थे। निर्जन वन में एक बार उनकी भेंट नारद मुनि से हुई तो नारद को बंदी बनाकर रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने पूछा कि तुम ऐसा निंदनीय कार्य आखिर करते क्यों हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तब नारद मुनि जी ने उनसे पूछा कि जिस परिवार के लिए तुम इतने पाप कर्म करते हो, क्या वह तुम्हारे इस पाप कार्य में भागीदार बनने के लिए तैयार होंगे? इसका उत्तर जानने के लिए रत्नाकर नारद मुनि को पेड़ से बांधकर घर पहुंचे और एक-एक कर परिवार के सभी सदस्यों से पूछा कि मैं डाकू बनकर लोगों को लूटने का जो पाप करता हूं, क्या तुम उस पाप में मेरे साथ हो? परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि आप इस परिवार के पालक हैं, इसलिए परिवार का पेट भरना तो आपका कर्तव्य है, इस पाप में हमारा कोई हिस्सा नहीं है।

सभी का एक ही उत्तर सुनकर रत्नाकर बहुत उदास हुए और नारद मुनि के पास पहुंचकर उनके पैरों में गिर पड़े। तब नारद मुनि ने रत्नाकर को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। रत्नाकर ने उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा तो नारद मुनि ने उन्हें 'राम' नाम जपने की सलाह दी लेकिन रत्नाकर ने कहा कि मुनिवर! मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं कि मेरे मुख से राम नाम का जाप नहीं हो पा रहा है। नारद मुनि ने उन्हें 'मरा-मरा' का जाप करने को कहा और इस प्रकार 'मरा-मरा' का जाप करते-करते रत्नाकर के मुख से अपने आप 'राम' नाम का जाप होने लगा। राम नाम में वह इस कदर लीन हो गए कि एक तपस्वी के रूप में ध्यानमग्न होकर वर्षों तक घोर तपस्या करने के कारण उनके शरीर पर चीटियों की बांबी लग गई। ऐसी कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए।

पौराणिक आख्यानों में यह उल्लेख भी मिलता है कि जब भगवान श्रीराम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही वनदेवी के नाम से निवास किया था और वहीं लव-कुश को जन्म दिया था, जिन्हें महर्षि वाल्मिकी द्वारा ज्ञान दिया गया। पहली बार सम्पूर्ण रामकथा लव-कुश ने ही भगवान श्रीराम को सुनाई थी। यही कारण है कि वाल्मिकी कृत रामायण में लव-कुश के जन्म के बाद का वृतांत भी मिलता है। बहरहाल, महर्षि वाल्मीकि के जीवन से यह सीख मिलती है कि जीवन की नई शुरूआत करने के लिए किसी खास समय या अवसर की आवश्यकता नहीं होती बल्कि इसके लिए आवश्यकता होती है केवल सत्य और धर्म को अपनाने की। उनका जीवन बुरे कर्मों को त्यागकर अच्छे कर्मों और भक्ति की राह पर अग्रसर होने की राह दिखलाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन समस्त मानव जाति को यही शिक्षा देता है कि मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, यदि वह चाहे तो अपनी हिम्मत, हौसले और मानसिक शक्ति के बल पर तमाम बाधाओं को पार कर सकता है।

संविधान बनाम सत्ता: जब सुप्रीम कोर्ट भी निशाने पर हो

सनत जैन

दोस्तों, यह भारत के लोकतंत्र का सबसे दर्दनाक दृश्य है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के भीतर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर किसी वकील द्वारा जूता उछाल दिया जाता है। यह तस्वीर सिर्फ एक अदालत का घोर अपमान या हमला नहीं, बल्कि संविधान पर सीधा प्रहार करती है। यह घटना हमारे उस भारत की आत्मा को झकझोर कर रख देती है जिसकी वैश्विक पहचान उसके संविधान से है। यह वही संविधान है, जो आम नागरिकों को समान अधिकार देता है, और यह वही संविधान है जो देश की तमाम शक्तियों के साथ ही सत्ता को सीमाओं में बांधता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई इस अकल्पनीय घटना ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं, कि क्या संविधान की मर्यादा बची रह गई है? गौर करें कि भारत में सत्ता और संविधान के बीच का संघर्ष कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरह आज संवैधानिक संस्थाएं एक-एक करके ढहती जा रही हैं, यह लोकतंत्र के लिए भयावह संकेत है। न्यायपालिका, जो अब तक विश्वास का आखिरी स्तंभ मानी जाती थी, उसी के भीतर असहिष्णुता और नफरत की राजनीति का प्रवेश हो जाना हमारी सामाजिक चेतना के पतन की निशानी है। घटना के प्रमुख पात्र बने वकील राकेश किशोर का यह कृत्य कोई एक व्यक्ति का आवेश नहीं था, बल्कि उस विषाक्त माहौल की उपज है जिसे पिछले कुछ वर्षों में सत्ता की सुविधा से पाला-पोसा गया। जब न्यायपालिका के फैसलों को धर्म, जाति या सत्ता के चश्मे से देखा जाने लगे, जब जजों की टिप्पणियां राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाएं, तब यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। एक अहम मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई ने जब कहा, कि मैं डरता नहीं हूं, कार्यवाही चलती रहनी चाहिए, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का साहस नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा की पुकार थी। तब भी सवाल तो यही है कि क्या अब देश के भीतर संविधान की व्याख्या सत्ता के हिसाब से की जा रही है? क्या संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता सिर्फ औपचारिकता बन कर रह गई है? इस दृष्य की निंदा के साथ ही देश में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बनाए रखना और लोगों को न्याय देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। पिछले 75 वर्षों में भारत की न्यायपालिका ने लोगों के बीच अपनी जो साख बनाई थी, अब वो परिस्थितियां बदल गई हैं और वर्तमान चुनौतीपूर्ण नजर आने लगा है। यह सच है कि अदालतों में निष्पक्षता और संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना अति-आवश्यक है। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव के चलते किसी भी तरह के फैसले प्रभावित न हों और संविधान और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए। इस घटना ने यह भी दिखाया कि न्यायपालिका का मौन और निष्पक्षता पर ध्यान न देने की स्थिति समाज में विद्रोह और असंतोष पैदा कर सकती है। ऐसे समय में न्यायपालिका को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने और न्याय की देवी के दृष्टिकोण से निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता है। कोर्ट में फैसले सुनाना न्यायाधीशों का काम है, लेकिन सुनना और तर्कों का मूल्यांकन करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह घटना देश की न्यायपालिका के लिए एक गंभीर चेतावनी और सुधार का अवसर भी है। आज ज़रूरत है आत्ममंथन की, कि क्या हम वाकई उस भारत में रह रहे हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों में था? या फिर हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां व्यक्तिगत सोच, धार्मिक आस्था और राजनीतिक हित संविधान से ऊपर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जूता उछाले जाने की घटना चेतावनी है कि अगर संविधान की गरिमा की रक्षा अभी नहीं हुई, तो आने वाली पीढ़ियां न्याय की इस पवित्र संस्था को इतिहास की किताबों में खोजती रह जाएंगी। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब हम संविधान के शब्दों में नहीं, उसकी भावना में विश्वास रखें।

भारत को अपने समुद्री सीमा को अधिक मजबूत करना होगा

संजय गोस्वामी

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के निर्णायक सैन्य जवाब के रूप में 07 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। कश्मीर में 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके और पाकिस्तानी क्षेत्र में 9 आतंकी स्थलों को निशाना बनाया,मई 2025 में पाकिस्तान के साथ भारत का हमला ऑपरेशन सिंदूर से वायु क्षेत्र में भारत की शक्ति में वृद्धि हुआ, इसलिए भारत ने पुराने मिग 21 विमान को अलविदा कर दिया बाद के घटनाक्रमों का ध्यान समुद्री क्षेत्र की ओर मोड़ दिया है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों की प्रमुख नौसैनिक गतिविधियों, क्षमता और आधिकारिक बयानों में देखा जा सकता है, जहाँ उनकी नौसेनाएँ अपनी स्थिति में सुधार कर रही हैं और युद्ध से निपटने के लिए तैयारी का संकेत दे रही हैं। 2 अक्टूबर को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 के युद्ध का हवाला देते हुए, पाकिस्तान को एक तीखी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी, जो भारत में किसी तरफ के आतंकवादी घटना में पाकिस्तान द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में उसके इतिहास और भूगोल को बदल सकती है लेकिन पाकिस्तान समुद्री क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढाँचे का विस्तार कर रहा है, यह एक ऐसा विकास है जो 2023 से जारी है। ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान को इस क्षेत्र में एक सैन्य बढ़त हासिल रही है। यह अगस्त में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी द्वारा दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य में किसी भी संघर्ष में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाली नौ सेना पहली सेना होगी।नौसेना से जुड़ी हाल की खबरें बताती हैं कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी 3डी निगरानी रडार लांजा-एन प्राप्त किया है, जो हवाई और सतह के लक्ष्यों का पता लगा सकता है। साथ ही, नौसेना को दो आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि को भी शामिल किया गया है, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया, जो हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना की स्थिति को देखते हुए यह डिज़ाइन किया गया है स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए पहले युद्ध पोत, आईएनएस निस्तार का शामिल होना और दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ भारत का पहला संयुक्त गश्ती दल की क्षमता व युद्ध पोत का निर्माण और हिंद-प्रशांत महासागर में में उसकी तैनाती दोनों को दर्शाता है, कि भारत की महासागर में पकड़ मजबूत है लेकिन पाकिस्तान भी जहाँ कराची और ग्वादर में चीन की उपस्थिति चिंता जनक है। पाकिस्तान ने अपने समुद्री सिग्नलिंग को हाल ही भी मजबूत किया है। मई में, उसने युद्ध में समुद्री आक्रमण से बचने के लिए कराची से ग्वादर तक समुद्र में युद्ध पोत की अपनी तैनाती बढ़ा दीं है। तब से, चीन द्वारा निर्मित हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बी, पीएनएस मैंग्रो का प्रक्षेपण किया है और घरेलू स्तर पर विकसित पी282 जहाज से प्रक्षेपित करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। इसके बाद भारत ने नोटिस टू एयरमैन को जारी किया जाता है जब हवाई यातायात की आवाजाही एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित होती है। , कई , मिसाइल का भी परीक्षण किया और लाइव-रीं अभ्यास भी हुए हैं - कभी-कभी केवल 60 समुद्री मील की दूरी पर - जिससे अरब सागर में अलर्ट और परिचालन का एक चक्र बना रहा है । नौसेना सिग्नलिंग का महत्व ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की गतिविधियों में वृद्धि एक बुनियादी सवाल उठाती है कि क्या ये समानांतर अभ्यास केवल नियमित गतिविधियाँ हैं या नौसेना क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान निरोध समीकरण में बदलाव का संकेत देने वाला एक सुनियोजित बल प्रदर्शन है। इसका उत्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा संकट, हालाँकि हवाई क्षेत्र में हल हो गया है, लेकिन समुद्र में रणनीतिक अनिश्चितता का एक अवशेष छोड़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और पाकिस्तान अपनी नौसैनिक स्थिति को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, न केवल प्रतिरोध के लिए, बल्कि इस संभावना के लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि टकराव का अगला चरण समुद्री क्षेत्र में सामने आ सकता है। इस बदलाव को क्षमताओं के व्यापक संतुलन के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। वायु क्षेत्र की तरह, समुद्री संतुलन को अब 1999 में कारगिल युद्ध में जीत मिली लेकिन समुद्र में उसकी शक्ति की कम थी जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह अमेरिका के युद्ध पोत जंग में भारत के लिए खतरा बना था जिसे रूस के युद्ध पोतों ने टाला था और भारत विजय हुआ लेकिन 26/11/08 में समुद्री मार्ग से पाकिस्तान के आतंकवादी का घुसना और मुंबई में कत्लेआम मचाना भी समुद्री मार्ग एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है । भारत की नौ सेना की ताकत कम नहीं है, लेकिन उसकी नौसैनिक क्षमता अब पुरानी होती जा रही है, जिससे आधुनिकीकरण की चिंताएँ बढ़ रही हैं पाकिस्तान लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, चीन द्वारा डिज़ाइन की गई पनडुब्बियों और तुर्की से बाबर श्रेणी के कोरवेट को शामिल कर रहा है। उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों और बहुमुखी वायु-रोधी और सतह-रोधी हथियारों के साथ, ये संपत्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। इस बदलाव को स्वीकार करते हुए, भारत के नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान की नौसेना की शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि की ओर भी इशारा किया था। हालाँकि भारत की बढ़त अभी भी बनी रह सकती है, लेकिन यह अंतर कम होता जा रहा है, जिससे हिंद महासागर में निर्विवाद प्रभुत्व की धारणाएँ और भी जटिल हो रही हैं। कुल मिलाकर, ये घटनाएँ तीन कारणों से महत्वपूर्ण हैं- तनाव नियंत्रण, बाहरी हस्तक्षेप और दोनों पक्षों के बदलते सिद्धांत। पहला, समुद्र में तनाव नियंत्रण कहीं अधिक कठिन है। हवाई झड़पों के विपरीत, जिन्हें संतुलित करके पीछे हटाया जा सकता है, किसी भी नौसैनिक मुठभेड़ (जहाज पर जहाज या जमीन पर जहाज) में युद्ध की दहलीज पार करने का जोखिम अधिक होगा।

1971 की यादें, जब भारतीय नौसैनिक अभियानों ने संघर्ष को निर्णायक रूप से बदल दिया था, अतिरिक्त संवेदनशीलता जोड़ती हैं - यहाँ तक कि सीमित समुद्री कार्रवाई भी पाकिस्तान की रणनीतिक कल्पना में अस्तित्व के जोखिम से जुड़ी है। तब से, पाकिस्तान की मुख्य समुद्री चिंता भारतीय नौसैनिक अभियानों के प्रति अपनी कमज़ोरी की पुनरावृत्ति को रोकना रही है, जो पहुँच-रोधी/क्षेत्र-निषेध क्षमताओं की खोज और निषेध द्वारा निवारण की ओर उन्मुख सिद्धांत की क्रमिक अभिव्यक्ति में दिखाई देती है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के ढाँचे के तहत ग्वादर के विकास को भी इसी निवारण तर्क के अंतर्गत समझा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देशों पर एफडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 63 औषधियों के सैंपल भेजे लैब

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशन पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पूरे राज्य में प्रतिबंधित और संदिग्ध कफ सिरप की बिक्री व वितरण के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है।

आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार के आदेशों के क्रम में प्रदेशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। एफडीए की टीमें विभिन्न मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों से सैंपल एकत्र कर परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं को भेज रही हैं।

प्रदेशव्यापी जांच की विस्तृत जानकारी साझा

एफडीए मुख्यालय देहरादून में अपर आयुक्त एवं औषधि नियंत्रक (ड्रग कंट्रोलर) ताजवर सिंह जग्गी ने पत्रकारवार्ता कर राज्य में संदिग्ध औषधियों की सैंपलिंग, जांच और बाजार नियंत्रण की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों के बीमार होने और मृत्यु की घटनाओं के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह कदम एहतियातन और जनहित में उठाया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ प्रदेश के हर जिले में संचालित किया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सभी जिलों में तेज हुई सैंपलिंग और जांच प्रक्रिया

अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में औषधि नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों से कफ सिरप के नमूने लेकर अधिकृत प्रयोगशालाओं को भेजें।

उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनियों से कच्चे माल जैसे पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल और अन्य रासायनिक तत्वों के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच की जा रही है, ताकि उत्पादन स्तर पर किसी प्रकार की गड़बड़ी या मिलावट की संभावना समाप्त की जा सके।

अब तक पूरे प्रदेश में 63 औषधियों के सैंपल एकत्र किए जा चुके हैं, जिनकी जांच प्रक्रिया जारी है। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बिना डॉक्टरी परामर्श बच्चों को दवा न दें

अपर आयुक्त ने जनता से अपील की कि वे बिना चिकित्सक की सलाह के बच्चों को कोई भी कफ सिरप या औषधि न दें। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। यदि बच्चे में सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें, तो केवल योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही दवा दी जाए।

उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और विभागीय टीमें इसकी सघन निगरानी कर रही हैं। प्रत्येक जिले में औषधि दुकानों और थोक विक्रेताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एफडीए का चेतावनी

अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि कई बार घरों में रखी खुली या पुरानी दवाइयाँ अपनी प्रभावशीलता खो देती हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाइयाँ तुरंत सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दी जाएँ और किसी भी खुली बोतल या अधूरी दवाई का प्रयोग न किया जाए।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि दवाइयाँ केवल चिकित्सक की सलाह पर ही उपयोग करें और हर दवा की समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) अवश्य जांचें, ताकि किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके।

मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश

अपर आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं इस अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उनके निर्देश हैं कि हर घर की थाली शुद्ध रहे और हर बच्चे का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है और औषधि व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में केवल गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ ही जनता तक पहुँचें।

दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों की भी सघन निगरानी

अपर आयुक्त ने बताया कि दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिठाइयों, दूध उत्पादों और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। राज्य की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी पर अंकुश लगाना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है।

जनहित में चल रहा यह अभियान

अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि एफडीए की यह कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की जनहित प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस अभियान की जानकारी पहुँचे और जनजागरूकता बढ़ाई जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल पहुंचकर डॉ. धन सिंह रावत की माता जी का हाल जाना

पथ प्रवाह, संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार देर रात्रि दून अस्पताल पहुंचे और कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की माता जी से भेंट कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से विस्तृत ब्रीफिंग लेकर आवश्यक उपचार और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने डॉ. धन सिंह रावत और उनके परिवार से मुलाकात की और माता जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि चिकित्सकीय प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की इस अचानक अस्पताल में उपस्थिति ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों को गहराई से प्रभावित किया।

अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सकगण भी इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और उपलब्ध उपचार संबंधी जानकारी दी। राज्य में इस संवेदनशील पहल की प्रशंसा की जा रही है, इसे मानवतावादी दृष्टिकोण और शासन के जिम्मेदार रवैये का प्रतीक बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज से निखरेगी खेल प्रतिभाएं

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और युवाओं को खेलों के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि उत्तराखंड में खेल संस्कृति को मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार की गई खेल अवसंरचना का नियमित रखरखाव और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन परिसंपत्तियों का अधिकतम लाभ खिलाड़ियों और युवाओं को मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्यभर में निरंतर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, जिससे खेल गतिविधियों को नई गति मिले और स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। श्री धामी ने विशेष रूप से हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से प्रदेश के खिलाड़ियों, विशेषकर युवाओं और महिला खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उत्तराखंड खेल जगत में एक नई पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर से लेकर विधायक, सांसद एवं

मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जाए, ताकि हर स्तर पर प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिले। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करे, ताकि उन्हें खेल और शारीरिक तैयारी के क्षेत्र में मजबूती मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन, छात्रवृत्ति, बीमा सुरक्षा और पुरस्कार की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट जगत की भागीदारी से खेल अवसंरचना के विकास को और गति दी जाए, ताकि खेल सुविधाओं का विस्तार गांव-गांव और शहर-शहर तक हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए और विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना की दिशा में तीव्रता लाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जाए।

बैठक में खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट, प्रमुख सचिव आरके. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, निदेशक खेल आशीष चौहान सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आईसीएफआरई की तकनीकों को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना प्राथमिकता: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

देहरादून में आईसीएफआरई की 31वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वेब पोर्टल और चार प्रकाशनों का विमोचन

पथ प्रवाह, देहरादून

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) की 31वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा आईसीएफआरई सोसायटी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने की।

इस अवसर पर आईसीएफआरई की महानिदेशक एवं सोसायटी की सदस्य सचिव श्रीमती कंचन देवी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत किए गए, जिन पर चर्चा के उपरांत सोसायटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इन दस्तावेजों को आगामी दिनों में संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईसीएफआरई के अनुसंधान कार्यों और उनके परिणामों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों और शोध निष्कर्षों को अंतिम उपयोगकर्ताओं – किसानों, वन प्रबंधकों और स्थानीय समुदायों – तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि वानिकी क्षेत्र में सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड वेब पोर्टल' का शुभारंभ किया, जो देशभर में मृदा की गुणवत्ता, संरचना और संरक्षण से जुड़ी जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही चार महत्वपूर्ण प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया –

- ■ कैसुरीना से कमाई- उच्च उपज देने वाली किस्में और नई खेती तकनीकें
- ■ आईसीएफआरई 2025-30 की विस्तार रणनीति
- ■ कम ज्ञात वनीय पौधों का संकलन- अंतर्दृष्टि और अवसर
- ■ भारत की प्रमुख वृक्ष प्रजातियों के लिए प्रजनन योजनाएँ

बैठक में आईसीएफआरई के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों के निदेशकों ने भी भाग लिया।

उत्तरकाशी में बाल अधिकार, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण पर विधिक जागरूकता अभियान का सफल आयोजन

डुण्डा के विद्यालयों में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सचिव सचिन कुमार ने दी ट्रांसजेंडर, बाल अधिकार और जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी

पथ प्रवाह, संवाददाता- ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के निर्देशन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के तत्वाधान में डुण्डा क्षेत्र के दो प्रमुख शिक्षण संस्थानों - सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज डुण्डा और द्रोणा जनविकास एकेडमी जूनियर हाई स्कूल डुण्डा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविर में सचिव सचिन कुमार ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों को राष्ट्रीय

विधिक सेवा प्राधिकरण की (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए) योजना 2024 के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नालसा की वर्तमान योजना के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों और नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करें। सचिन कुमार ने छात्रों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार, लैंगिक समानता, और समाज के प्रत्येक स्तर पर समान भागीदारी के महत्व पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को लैंगिक भेदभाव मुक्त वातावरण में जीने और अपनी पहचान के सम्मान का अधिकार है। शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, भारतीय ध्वज संहिता, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षित दवा - सुरक्षित जीवन अभियान, दिव्यांगजन कल्याण योजनाएं, यू.डी.आई.डी. कार्ड, और शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के लिए सरकारी सहायता कार्यक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर सचिव सचिन कुमार के साथ रिटेनर अधिवक्ता, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, जिला बाल सम्प्रेक्षण गृह डुण्डा के अधीक्षक, पराविधिक कार्यकर्ता, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सचिन कुमार ने कहा, विधिक साक्षरता ही सामाजिक सशक्तिकरण का आधार है। जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं, तभी एक न्यायसंगत और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है।÷

गंगोत्री धाम यात्रा पर सीओ उत्तरकाशी का निरीक्षण प्रातः 4 से सांय 4 बजे तक ही होगी यात्रियों की आवाजाही, बारिश अलर्ट पर सतर्क रहने के निर्देश

पथ प्रवाह, संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ावों में से एक गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक सिंह पंवार ने यात्रा सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हीना स्थित यात्री पंजीकरण केंद्र पर ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से मुलाकात की तथा यात्रा संचालन में सतर्कता और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। सीओ पंवार ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि तीर्थयात्रियों की आवाजाही केवल प्रातः 4 बजे से सांय 4 बजे तक ही कराई जाए, ताकि रात्रिकालीन दुर्घटनाओं और मौसम संबंधी जोखिमों से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा जारी वर्षा अलर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मी पूरी चौकसी बरतें और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थलों पर रोका जाए। निरीक्षण के दौरान सीओ ने यात्रा मार्ग पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं, यातायात नियंत्रण और पंजीकरण प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन किया।

उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए हर पुलिसकर्मी का दायित्व है कि वह अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति न बने, इसके लिए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जिलाधिकारी ने वाइब्रेंट विलेज अध्ययन लौटे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से साझा किए शासन के जमीनी अनुभव

पथ प्रवाह, संवाददाता-ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिला मुख्यालय में सोमवार को आयोजित विशेष संवाद सत्र में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 42 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ सतत विकास और नीति निर्माण पर गहन विचार-विमर्श किया। यह सत्र प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें जिलाधिकारी ने आधुनिक शासन प्रणाली में सतत विकास की भूमिका को केवल नीति नहीं बल्कि प्रशासनिक आवश्यकता बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज की प्रशासनिक व्यवस्था में सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास की हर प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को शामिल करना ही सच्चे सुशासन की पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतियों की सफलता केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असली

मूल्य तब नापी जाती है जब उसका प्रभाव गांवों, पहाड़ों और सीमांत क्षेत्रों के जनजीवन में दिखाई दे।

जरूरतमंद तक न्याय की पहुंच, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया निरीक्षण और मूल्यांकन

पथ प्रवाह, संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। समाज के कमजोर वर्गों को न्याय तक सहज पहुंच और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी की ओर से बाल सम्प्रेक्षण गृह, वृद्धाश्रम, किशोर न्याय बोर्ड और विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी डुण्डा का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला जज व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के निर्देशन में संपन्न हुआ। निरीक्षण दल का नेतृत्व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार ने किया। निरीक्षण के दौरान सचिव सचिन कुमार ने बाल सम्प्रेक्षण गृह डुण्डा के प्रभारी अधीक्षक से वार्ता की और

निर्देश दिए कि यदि किसी विधि-विवादित किशोर को निःशुल्क विधिक सहायता या अधिवक्ता की आवश्यकता हो, तो उसका आवेदन तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा जाए ताकि ऐसे किशोर को शीघ्र अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। अधीक्षक ने जानकारी दी कि वर्तमान में गृह में एक विधि-विवादित किशोर निरूद्ध है। इसके साथ ही वृद्धाश्रम डुण्डा का भी निरीक्षण किया गया, जहां दो वरिष्ठ नागरिक निवासरत हैं। सचिव ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों के भोजन, स्वास्थ्य जांच और आवासीय सुविधाओं को व्यवस्थित और मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

49 देशों के 627 प्रतिभागी, 682 वैज्ञानिक योगदान के साथ आईएएचएस की 12वीं वैज्ञानिक सभा का हुआ भव्य शुभारंभ

पथ प्रवाह,रुड़की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की सोमवार को वैश्विक जल विज्ञान समुदाय का केंद्र बन गया, जब यहां अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संघ (आईएएचएस) की 12वीं वैज्ञानिक सभा का उद्घाटन हुआ। यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ, जिसमें 49 देशों के 627 से अधिक प्रतिभागियों और 682 वैज्ञानिकों ने भागीदारी दर्ज की – जिससे यह आईएएचएस के इतिहास की सबसे बड़ी सभाओं में से एक बन गई।

मुख्य अतिथि, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि ÷जल विज्ञान, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सतत विकास का आधार है। आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान वैश्विक ज्ञान को स्थानीय समाधानों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे समुदायों और नीति निर्माताओं

दोनों को सशक्त बनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन एवं आईआईटी रुड़की कुलगीत के साथ हुई। इसके बाद मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत, आईएएचएस के अध्यक्ष प्रो. साल्वातोरे ग्रिमाल्डी, आईएनएसए के उपाध्यक्ष एवं सीएसआईआर-एनईआईएसटी के निदेशक डॉ. वी.एम. तिवारी, आईएएचएस एसए 2025 के अध्यक्ष प्रो. सुमित सेन और संयोजक प्रो. अंकित अग्रवाल ने सम्मेलन के महत्व और इसकी वैश्विक उपयोगिता पर अपने विचार रखे। प्रो. पंत ने कहा कि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह छह दिवसीय सभा नए विचारों, दीर्घकालिक साझेदारियों और परिवर्तनकारी नवाचारों को प्रेरित करेगी, जो जल विज्ञान एवं समाज दोनों के लिए सार्थक योगदान देंगी। सत्र के दौरान आईएएचएस वैज्ञानिक सभा 2025 की कार्यवाही का औपचारिक विमोचन भी किया गया, जो एक सप्ताह तक चलने वाले वैज्ञानिक विचार-विमर्श, तकनीकी सत्रों, प्रदर्शनी एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोगों की शुरुआत का प्रतीक रहा। यह आयोजन वैश्विक स्तर पर जल स्थिरता एवं जलवायु अनुकूलन पर सार्थक चर्चा, सतत जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उपायों, तथा नवाचारों को साझा करने का मंच बना। आईआईटी रुड़की में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सभा भारत की वैश्विक जल विज्ञान अनुसंधान और सतत जल प्रबंधन में अग्रणी भूमिका को और सुदृढ़ करती है। इस अवसर पर वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने मिलकर यह संकल्प भी लिया कि आने वाले समय में जल संसाधन प्रबंधन को और अधिक टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए विश्व स्तर पर सहयोग को बढ़ाया जाएगा।

एक नजर

एचोली से कुमौड़ तक हाईवे की दुर्दशा पर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार का जताया विरोध

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़। उत्तराखंड क्रांति दल पिथौरागढ़ द्वारा ऐचोली तिराहे पर नेशनल हाईवे की दुर्दशा के विरोध में और शीघ्र उसका निर्माण किए जाने की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष तथा महानगर अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में नेशनल हाईवे प्रशासन तथा उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने हाईवे की दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कठोर शब्दों में रोष व्यक्त किया और कहा कि अंधाधुंध पैसा खर्च किए जाने के बावजूद भी हाईवे की ऐसी हालत बड़ी चिंताजनक है। एचोली से कुमौड़ तक लोगों का पैदल चलना, वाहन चलाना तथा स्कूली बच्चों का सड़क पर चलना बड़ा कठिन हो गया है ।हर समय दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। लगातार उड़ती धूल के धुंध से दुकानदारों और स्थानीय पैदल चलने वाली जनता में अनेक बीमारियां पैदा होने लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने मांग की कि क्षतिग्रस्त सड़क का शीघ्र निर्माण कर नया बनाया जाए ताकि लोगों के चलने में सुविधा हो ।लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके ।इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल कल सोमवार एक ज्ञापन जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजेगा और उसके माध्यम से भी मांग की जाएगी कि शीघ्र खस्ता हाल सड़क में डामरीडरण किया जाए। पुतला दहन करने वालों में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जगत मेहता, जिला महामंत्री मदन पोखरिया, युवा नेता हरिओम मुनोला, युवा नेता महेश पाल, भूतपूर्व सैनिक नेता कप्तान बोरा, समाजसेवी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजेश पांडे, पीतांबर पांडे, युवा समाज सेवी आनंद मल, युवा नेता मनोज भंडारी सहित भारी संख्या में स्थानीय जनता ने भाग लिया।

वारण्टी को गाजियाबाद से किया गिरफ्तार

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली झूलाघाट संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त नवीन कुमार पुत्र स्व. हरी राम निवासी सेठीगांव मजिरकांडा को शक्तिखण्ड, इन्दिरापुरम गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध दो मारपीट के मामले में धारा 323/504/506 भादवि और चैक बाउन्स के मामले में 138 एन.आई. एक्ट के तहत वाद न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा कई बार समन भेजे जाने के बावजूद अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ, जिस कारण अदालत द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्त को आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

गुमशुदा महिला गाजियाबाद से और युवती नगीना से बरामद

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत से लापता महिला और एक युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 20 सितम्बर एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उनकी पुत्री के बिना बताए कहीं चली गई है। सूचना के आधार पर कोतवाली बेरीनाग में गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की गई। उपनिरीक्षक पूजा मेहरा द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। इसी क्रम में एक अन्य महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी थी जिसकी विवेचना अपर उ0नि0 भुवन पाण्डे द्वारा की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के आदेशानुसार एवं पुलिस उपाधीक्षक के0एस0रावत के पर्यवेक्षण में गुमशुदा बालिका की तलाश हेतु गंभीर प्रयास शुरू किए गए। प्रभारी कोतवाली बेरीनाग हरीश सिंह के नेतृत्व में विवेचक अपर उ0नि0 भुवन पाण्डे द्वारा सर्विलांस सैल की मदद से टैक्निकल व मैनुअल इनपुट्स के आधार पर लगातार प्रयास करते हुए अंततः एक महिला को गाजियाबाद से तथा दूसरी को नगीना उ0प्र0 से बरामद कर लिया।

दीपावली से पूर्व जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें लगभग 55 नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर ही करते हुए स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा।

जनसुनवाई में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए, साथ ही यह भी कहा गया कि मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के पिथौरागढ़, अस्कोट, डीडीहाट, धारचूला और बेरीनाग क्षेत्र के अधिकारियों से जनपद की सड़कों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, ताकि आमजन को त्योहार के दौरान आवागमन में कोई असुविधा न हो।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत निर्माणाधीन अथवा क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की गई। सुशासन पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर आवश्यक डेटा अपलोड नहीं किया गया है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित डाटा तत्काल प्रभाव से अपडेट किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल पर समयबद्ध और नियमित डेटा प्रविष्टि सुशासन के लिए अनिवार्य है, और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, तकनीक और विकास संस्कार का संगम

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़

सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मानव मंदिर गुरूकुल, दिल्ली ने सीमा जागरण मंच के सहयोग से सीमांत अंचलों के विद्यालयों को लैपटॉप प्रदान किए हैं। इस अभियान के तहत पिथौरागढ़ जिले के चार प्रमुख विद्यालय – वात्सल्यम एकेडमी, विण, चिल्ड्रेन पैराडाइस स्कूल, अस्कोट (कनालीछीना), आस्था एकेडमी, बरम (धारचूला) तथा अभिलाषा एकेडमी, डीडीहाट– को लैपटॉप भेंट किए गए। दिल्ली स्थित सराय काले खां के मानव मंदिर गुरूकुल की साध्वी समता श्री माता जी ने यह लैपटॉप सीमांत विद्यालयों को सौंपते हुए कहा कि ÷हमारा उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से समान अवसर प्रदान कर उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। शिक्षा का अधिकार तभी पूर्ण होता है, जब तकनीक हर बच्चे तक पहुंचे। यह पहल सीमा जागरण मंच के वरिष्ठ समाजसेवी रमेश जी भाई साहब जोशी के मार्गदर्शन में चल रहे ÷शैक्षिक संसाधन सुदृढ़ीकरण अभियान÷ का हिस्सा है, जिसके माध्यम से सीमांत विद्यालयों को तकनीकी संसाधनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सिविल सोसायटी अभिलाषा समिति, पिथौरागढ़ के निदेशक एवं समाजसेवी डॉ. किशोर कुमार पंत ने बताया कि मानव मंदिर गुरूकुल एक आवासीय संस्था है, जो अनाथ, वंचित और जरूरतमंद बच्चों को समग्र शिक्षा, संस्कार और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत अभिलाषा समिति, पिथौरागढ़ को भी आठ लैपटॉप प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. पंत ने बताया कि आगामी 24 अक्टूबर 2025 से अभिलाषा आईटी प्वाइंट नामक एक निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा, जो मानव मंदिर गुरूकुल के मार्गदर्शन में संचालित होगा।

यह केंद्र सीमांत क्षेत्रों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे वे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ सकेंगे। साध्वी समता श्री माता जी ने इस अवसर पर कहा कि मानव मंदिर गुरूकुल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, नैतिकता और डिजिटल जागरूकता के संस्कार विकसित करना है।

लिव इन रिलेशन पारंपरिक आस्थाओं मान्यताओं पर कुठाराघात

जीवन सिंह बोहरा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार।

भारत एक धार्मिक आधारित सामाजिक परंपरा और रीति रिवाजों का देश है यहां पर जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक हर एक संस्कार आधारित सामाजिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बीच में शादी विवाह भी एक 12वें नं0 का संस्कार है। जिसमें सारा समाज का ताना बाना टिका है परंतु अब सामाजिक परंपराओं मान्यताओं को इस बदलते वैज्ञानिक आधारित समय में इस तरह से रिश्तों को तार तार कर देने वाले मूल्य हैं। अर्थहीन सामाजिक नियमों को जनता के ऊपर थोप देना कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता वाले कथा कथित पढ़े लिखे कानून निर्माता इस तरह से सामाजिक परंपराओं का परिहास एवं रिश्तो को तार तार करने वाला नियम बनाकर समाज एक विकृत पहल को जन्म देकर समाज को खंडित खंडित कर रही है। स्वयं सरकार द्वारा सामाजिक परंपराओं विनाश किया जा रहा है जब हमारे संस्कृतियों में जो हिंदुओं की संस्कृति है खास तौर पर उसमें एक शादी सात जन्म तक का रिश्ता है तो यह बिना शादी के लिविंग रिलेशन में रहना कहां की औचित्यता है। भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जो सात जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा (यूसीसी) के अंतर्गत बनाए गए नियमो में लिव-इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने और समाज में ऐसे लागू करने से सामाजिक परंपराओं पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में छ्ष्ट लागू किया है, जिसमें विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शामिल है। इसके अलावा, यह कानून लिव-इन रिलेशनशिप और शादी से जुड़े नियमों में बदलाव लाता है। इस कानून के तहत विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति के जीवित रहते दूसरी शादी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिससे शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी। परंतु इस कानून में ही तो खामी ही है वह हमारी सामाजिक बुराइयों की तरफ ले जाता है माना कि उनका अधिकार है किसी को भी कहीं इसका मतलब यह नहीं कि हम सीमा से बाहर निकल जाए और यह कानून मान्यता और परंपराओं को तक में रखकर बनाया गया है। लिव-इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग बिना शादी के साथ रहते हैं। यह व्यवस्था भारतीय समाज में एक नई चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि यह पारंपरिक विवाह के विपरीत है। कुछ लोगों का मानना है कि यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है, जबकि अन्य इसे सामाजिक बंधनों के लिए खतरा मानते हैं कुछ लोग इस रिलेशनशिप के नियम को रिलेशन हीन नियम भी कहते हैं।

उत्तराखंड में CC के रिलेशन वाले कानून लागू करने से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। उत्तराखंड में UCC लागू करने से कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं और इसे लागू करते समय यह भी कहा है कि सामाजिक बदलाव लाने के यह कदम उठाया गया है परंतु क्या हमारी परंपराओं को उजाड़ कर उसमें सेंधमारी कर यह बदलाव लाना जरूरी था? सामाजिक बदलाव UCC के तहत विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों में बदलाव से सामाजिक बदलाव आ सकता है। कहा जाता है कि यह UCC महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद कर सकता है, खासकर संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में परंतु हम इस पर यह विचार रखते हैं की क्या महिलाओं का अधिकार अपनी संस्कृति धरोहर मूल्यों को तक में रखकर ही मिल सकता है आने वाले समय में यह परंपरा पारंपरिक मूल्यों पर बुरा प्रभाव डालेगी UCC पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक बंधनों पर प्रभाव डाल सकता है, खासकर विवाह और परिवार के संदर्भ में।

राज्य स्थापना की रजत जयंती पर उत्तरकाशी में होगा साहित्यकारों का समागम

सूचना क्रांति के युग में साहित्यिक विमर्श थीम पर होगा आयोजन

पथ प्रवाह, संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जनपद में राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्थानीय साहित्यकारों को एक साझा मंच देने की पहल शुरू की गई है। जिलाधिकारी की विशेष पहल पर सूचना क्रांति के युग में साहित्यिक विमर्श विषय पर साहित्यिक समागम का आयोजन किया जाएगा।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी के.के. जोशी ने जानकारी दी कि यह समागम 2 से 9 नवम्बर 2025 के बीच जिला प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जनपद के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा तथा उनकी साहित्यिक कृतियों का प्रदर्शन एवं विमोचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केवल उत्तरकाशी जनपद के स्थायी निवासी साहित्यकार ही इस आयोजन में भाग लेने के पात्र होंगे। पंजीकरण के लिए साहित्यकारों को ऑनलाइन वेब लिंक https://forms.gle/DX15&PXcD22su2UT8 के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी के अनुसार, इस समागम का उद्देश्य स्थानीय रचनाकारों को प्रोत्साहन देना, उत्तरकाशी की साहित्यिक धरोहर को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में रचनात्मक लेखन की दिशा में संवाद स्थापित करना है।

उत्तराखंड पुलिस ने साइबर सुरक्षा में दिखाया राष्ट्रीय स्तर पर दम, 47 करोड़ पीड़ितों को लौटाए

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण और पीड़ितों के आर्थिक संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। वर्ष 2021-25 में राज्य में साइबर अपराधों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड पुलिस ने 47.02 करोड़ से अधिक की राशि पीड़ितों को वापस करवाई, जो उत्तर भारत के राज्यों में सर्वोच्च प्रदर्शन में शामिल है।

अंतरराज्यीय सहयोग और दोषसिद्धि दर में राष्ट्रीय श्रेष्ठता

उत्तराखंड पुलिस ने अंतरराज्यीय नेटवर्क पर सक्रिय कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों के आरोपी शामिल हैं। देशभर में संचालित अभियानों 'ऑपरेशन प्रहार' और 'ऑपरेशन हेली' के तहत सैकड़ों वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर और बैंक खाते ब्लॉक किए गए, साथ ही कई सोशल मीडिया विज्ञापन हटा दिए गए। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में दर्ज मामलों में औसतन 87% आरोपियों को चार्जशीट किया गया, जबकि दोषसिद्धि दर 64.7% रही, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी से अधिक है।

प्रमुख साइबर ठगी प्रकरणों में सफलता

साइबर थाना देहरादून और उधमसिंहनगर ने वर्ष 2023-24 में 20 से अधिक राज्य स्तरीय और अंतरराज्यीय ठगी मामलों को सफलतापूर्वक निस्तारित किया। इनमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं:

फेक ट्रेडिंग ऐप, फिशिंग लिंक, OTP फ्रॉड, PI ठगी

इसके अतिरिक्त, बिहार, झारखंड और दिल्ली-एनसीआर नेटवर्क से जुड़े दर्जनों

त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटी हरिद्वार पुलिस

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। त्योहारी सीजन पर सुरक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता एवं समन्वय बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद हरिद्वार की विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा ज्वेलरी शॉप मालिकों के साथ बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिये गए।

बैठक में शॉप मालिकों को अपनी दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, दुकानों के बाहर एवं अंदर लगे छ्ष्ट्ठ्ठ्ठ कैमरों को सुचारू रूप से कार्यशील रखने, कैमरों की रिकॉर्डिंग नियमित रूप से जांचने, सुरक्षा गार्ड एवं डेटा बैकअप सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार पुलिस ने सभी व्यवसायियों से अनुरोध किया कि भीड़भाड़ वाले समय में सतर्कता बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा बाजारों, सर्राफा गलियों एवं प्रमुख व्यावसायिक स्थलों पर गश्त व निगरानी बढ़ाई जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, सहयोग करें और किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नज़दीकी थाना/चौकी को दें।

हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे में पकड़े तीन वाहन चोर, चोरी के 4 वाहन बरामद

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस ने 24 घण्टें के भीतर वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन अन्तर्राज्जीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 वाहन बरामद हुए हैं।

थाना श्यामपुर पुलिस के मुताबिक 05.10.2024 को वादी राजेन्द्र सिह निवासी ग्राम कांगडी थाना श्यामपुर हरिद्वार द्वारा अपनी मो0सा0 चोरी के सम्बंध में मु0अ0स0 102/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। उक्त चोरी गये वाहनों की बरामदगी एवं वाहन चोरो की तलाश हेतु थानाध्यक्ष थाना श्यामपुर के नेतृत्व में थाना स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित कर टीमों को अलग-अलग टास्क देकर आस-पास के थाना क्षेत्र व सरहदी जनपद के थानों में भेजा गया। घटनास्थल के आस-पास

इलेक्ट्रानिक माध्यम से एवं चोरी गये वाहन की तलाश हेतु थाना क्षेत्र में लगातार स्थान बदल-2 कर पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग की कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्ति आते दिखायी दिये। उन्हें रोककर पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम हिमांशु कुमार पुत्र मुन्नू सिंह निवासी ग्राम रामदासवाली थाना मण्डावली जिला बिजनौर, ओमप्रकाश पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम शाहपुरा रत्न थाना कीरतपुर जिला बिजनौर ओर अर्पित पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम धारीवाला थाना पथरी जिला हरिद्वार बताया। उनके पास मौजूद बाइक चोरी की निकली। आरोपियों से पुलिस टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ पर इनके द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी किये दुपाहिया वाहनों को नीलधारा के पास झाडियो मे छिपाया होना बताया गया। जिसके बाद पुलिस टीम ने इनकी निशानदेही पर 3 अन्य बाइक और एक स्कूटी के खुले हुये पार्टस बरामद किये।

अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़े चार ट्रैक्टर ट्राली

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। कोतवाली मंगलौर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत चार ट्रैक्टर ट्राली अवैध खनन सामग्री के साथ सीज किये। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के लिए थाना स्तर पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आमखेडी मे सोनाली नदी में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। खनन माफिया पुलिस को आता देख अंधेरा का फायदा उठाकर वाहनों को छोडकर मौके से भाग गये। टीम द्वारा मौके से

अवैध खनन लदे 4 ट्रैक्टरों को कब्जे मे लेकर सीज किया गया। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ट्रैक्टर किसके है इसका पता लगाकर इनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जनजातीय क्षेत्र गमशाली के दम्फूधार में 11 अक्टूबर को होगा बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर

पथ प्रवाह, संवाददाता

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को जनजातीय क्षेत्र गमशाली के दुंफूधार में एक बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पुनीत कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुनीत कुमार ने बताया कि यह शिविर माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगा। इस अवसर पर विधिक जानकारी के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाकर सरकार की संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी उपलब्ध कराया

जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों को विधिक जागरूकता के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की उपयोगी जानकारी के साथ स्टॉल लगाएं तथा ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान करें। सचिव पुनीत कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें और विधिक जानकारी के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

एक नजर

ज्वालापुर में विजिलेंस टीम छापेमारी कर पकड़ी 17 स्थानों पर बिजली चोरी

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। देहरादून से आई विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने ज्वालापुर स्थित विष्णु लोक कॉलोनी, अहबाब नगर और मोहल्ला घोसियान में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 17 स्थानों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े। सभी मामलों में कोतवाली ज्वालापुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपखंड अधिकारी अर्चना एवं अवर अभियंता मुकेश रवि ने बताया कि पिछले कई दिनों से इन क्षेत्रों में बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। सूचनाओं के आधार पर दोपहर छापेमारी की गई, जिसमें बिजली चोरी के मामले सामने आए। छापेमारी अभियान में देहरादून से आए विजिलेंस अधिकारियों ने भी भाग लिया। विद्युत विभाग ने इन मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी रोकने के लिए इस तरह की छापेमारी नियमित रूप से जारी रहेगी। इस औचक कार्रवाई से इलाके में बिजली चोरी करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस छापेमारी ने यह साफ कर दिया है कि बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस टीम और विद्युत विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इससे न केवल राजस्व की हानि को रोका जा सकेगा, बल्कि बिजली की आपूर्ति में सुधार भी होगा।

एसएसपी से लगायी जानमाल की सुरक्षा की गुहार

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित जुर्स कंट्री में रहने वाली महिला ने कुछ लोगों पर उधार के पैसे नहीं देने और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी व झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़िता और उसके परिजनों ने एसएसपी को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला शिप्रा ने बताया कि उनके पति ने एक व्यक्ति को करीब 1,35,000 उधार दिए थे। उन्होंने जब उधार के पैसे वापस मांगे तो आरोपी इनकार करने लगा। पिछले एक साल से व्यक्ति और उसके दो साथी उन्हें झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी भी देते आ रहे है। पीड़िता के पति अंकुर कर्णवाल ने उनकी कई जगह शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीती चार अक्टूबर की रात को भी तीनों लोग उनके घर आए और अभद्रता करने लगे और शिकायत वापस करने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगायी है।

बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने चलाया चैकिंग अभियान

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। बिना नंबर प्लेट के यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वर्तमान समय में जनपद में त्यौहारों का सीजन चल रहा है जिसके दृष्टिगत बाजारों/सडकों पर काफी भीड़ है। सूचना मिल रही थी कि इसी भीड का फायदा उठाकर कुछ लोग यातायात के नियमो का उल्लंघन कर वाहनों को बिना लाईसेंस, बिना कागजात, बिना नम्बर प्लेट के चला रहे हैं। क़स्बा मंगलौर में ऐसे वाहनों के खिलाफ चैकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में करीब एक दर्जन से ज्यादा बिना नम्बर प्लेट की गाडियों को सीज किया गया और करीब 24 वाहनों को कोर्ट व नगद संयोजन शुल्क में चालान किये गये। एक दर्जन से अधिक बिना नम्बर प्लेट के वाहनों पर नम्बर प्लेट लगवायी गयी। प्रभारी अमरजीत सिंह ने इस दौरान सभी को अपने वाहनों पर सही नम्बर प्लेट लगवाकर यातायात के नियमों का पालन कर वाहनों को चलाने की हिदायत दी गई।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालयः 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन–249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई– www.pathpravah.com